

जा० वि०
30.6.10

प्रेषक,

एस० राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 :

देहरादून: दिनांक-30 जून, 2010

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित नवीन योजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन योजनाओं की घोषणा की गयी है :-

- 1- मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना।
- 2- मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार योजना।
- 3- पं० दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग एवं वायबिलिटी गैप योजना

उक्त योजनाओं के विस्तृत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनायें तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही हैं। अतएव योजनाओं से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों की प्रतियां सभी नगर निकायों/जिलाधिकारियों/आयुक्तों को प्रेषित करते हुए योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

योजनाओं की सॉफ्ट कापी (सीडी) संलग्न है। अतएव पुस्तिका के रूप में दिशा निर्देश की आवश्यक प्रतियां तैयार करा ली जाय एवं मा० मुख्यमंत्री कार्यालय तथा शासन हेतु 100 प्रतियां पृथक से भी उपलब्ध करा दी जाय।

भवदीय,

संलग्न:-यथोक्त।


(एस० राजू)
प्रमुख सचिव।

सं० 64 (1)/IV(2)-श०वि०-10, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, शहरी विकास को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन को अवस्थापना विकास आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त योजनाओं के दिशा-निर्देश (सीडी संलग्न) सहित नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(निधिमणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत

मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार योजना

दिशा निर्देश-2010



उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन

मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार योजना

1. प्रस्तावना

नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम, 2000 तथा राष्ट्रीय स्वच्छता नीति, 2008 के अनुरूप कार्यवाही करते हुए शहर को स्वच्छ बनाने तथा खुले में गन्दगी से मुक्त (open defecation free) करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की जा रही है।

2. उद्देश्य

इस योजना के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा segregation at source, door to door collection/shop to shop collection/establishment to establishment collection, जैविक अपशिष्ट का treatment, अजैविक अपशिष्ट की recycling & reuse तथा शेष बचे अपशिष्ट का वैज्ञानिक भू-भरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वच्छता नीति के अन्तर्गत कार्यवाही द्वारा पूरे नगरीय क्षेत्र open defecation से मुक्त करने और समस्त शौचालय सुरक्षित प्रकृति बनाने में सराहनीय कार्य करने पर उच्चतम रेटिंग प्राप्त करने वाली नगर निकायों को पुरस्कृत किया जायेगा।

3. योजना का अनुश्रवण:-

- 3.1 पुरस्कार योजना के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य एवं नगर निकायों को सफाई एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रस्तर-2 के उद्देश्यों की पूर्ति के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रत्येक माह सभी नगर निकायों के सम्बन्ध में प्रस्तर-7 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास एवं मण्डलायुक्त को प्रेषित करेंगे।
- 3.2 मण्डलायुक्त द्वारा प्राप्त मासिक रिपोर्ट के आधार पर निकायों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए प्रत्येक त्रैमास में अपनी रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3.3 निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा भी नगर निकायों का आकस्मिक निरीक्षण भी समय-समय पर किया जायेगा तथा अपनी रिपोर्ट पुरस्कार के लिए संस्तुति के समय अंकित की जायेगी।

4. अनुदान की सीमा:-

योजनान्तर्गत निम्न अनुदान की सीमा निर्धारित की गयी है:-

- 4.1 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाली नगर निगम/नगर पालिका परिषद को क्रमशः रू0 50.00 लाख, 25.00 लाख तथा 10.00 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा।
- 4.2 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाली नगर पंचायत को क्रमशः रू0 25.00 लाख, 20.00 लाख तथा 10.00 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा।
- 4.3 पुरस्कृत नगर निकायों को पुरस्कार की धनराशि के 90 प्रतिशत धनराशि का उपयोग स्वच्छता कार्यो/सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं 10 प्रतिशत धनराशि का उपयोग सम्बन्धित स्वच्छता कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत करने में व्यय किया जा सकेगा, परन्तु किसी भी दशा में कर्मचारी को दी जाने वाली धनराशि उसके एक माह के वेतन से अधिक न हो तदोपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष धनराशि का उपयोग नगर निकाय अपनी निधि के रूप में कर सकता है। पुरस्कृत धनराशि के उपयोग की मानिट्रिंग सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

5. वित्तीय व्यवस्था

योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति उत्तरांचल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि के अन्तर्गत प्राविधानित बजट से की जायेगी।

6. परियोजना की संस्तुति/स्वीकृति की प्रक्रिया:-

- 6.1 योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य करने वाली नगर निकायों को पुरस्कृत करने हेतु नगर निकायों द्वारा अपने आवेदन सम्बन्धित जिलाधिकारी की संस्तुति सहित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, शहरी विकास को प्रत्येक वर्ष के माह सितम्बर की 30 तारीख तक उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 6.2 जिलाधिकारी द्वारा निकाय के चयन हेतु प्रस्तर-7.1 में अंकित मानकों पर आधारित परफॉर्मेस/संकेतको के अन्तर्गत उनके सम्मुख अंकित अंको में से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा, जो कि कुल 200 अंकों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली निकाय को ही इसके लिए योग्य मानते हुए पुरस्कार योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

- 6.3 निदेशक, शहरी विकास की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जो पुरस्कार के सम्बन्ध में निर्णय लेने से पूर्व आवश्यक प्रश्नावली तैयार कर सम्बन्धित निकायों को प्रेषित करेगी तथा प्राप्त उत्तर का परीक्षण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।
- 6.4 उक्त समिति में निदेशालय के एक अन्य अधिकारी के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक स्तर का हो तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नामित एक अधिकारी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सम्बन्ध में निदेशक, शहरी विकास द्वारा नामित एक तकनीकी विशेषज्ञ होंगे।
- 6.5 जिलाधिकारियों की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निदेशक शहरी विकास की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति द्वारा प्रस्तर-7.1 में उल्लिखित मानकों के सम्मुख अंकों के आधार पर किया जायेगा तथा प्रस्तर-7.2 में उल्लिखित मानकों का संज्ञान लेते हुए परीक्षण करने के उपरान्त नगर निकायों द्वारा प्राप्त रेटिंग सहित पुरस्कार हेतु संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को माह दिसम्बर तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- 6.6 निदेशक, शहरी विकास की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी है, के भ्रमण एवं अन्य अनुसांगिक व्ययों के लिए कुल पुरस्कार की धनराशि रु0 140.00 लाख के अतिरिक्त रु0 5.00 लाख का प्राविधान शासन द्वारा बजट में किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित व्ययों के अभिलेखों सहित पुरस्कार के अन्तिम निर्णय के साथ-साथ शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।

7. मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार हेतु पात्रता के मानक

मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार हेतु निकाय का चयन प्रस्तर-7.1 में अंकित मानकों पर आधारित परफॉर्मेंस/संकेतको के अन्तर्गत उनके सम्मुख अंकित अंको के आधार पर एवं प्रस्तर-7.2 में अंकित संकेतक बिन्दुओं को भी परफॉर्मेंस के रूप में, संज्ञान में लिया जायेगा—

7.1 चयन हेतु मानक

- a. निकाय में कूड़े-कचरे के उचित प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 तथा राष्ट्रीय स्वच्छता नीति, 2008 के अनुरूप सिटी सैनिटेशन प्लान बनाये जाने की स्थिति।

(10 अंक)

- b. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 तथा राष्ट्रीय स्वच्छता नीति, 2008 के अनुरूप सिटी सैनिटेशन प्लान के

क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु किये गये प्रयास।

(10 अंक)

- c. सफाई व्यवस्था के लिए शहर को सैक्टर में बांटकर अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही, जिसमें सफाई निरीक्षक इत्यादि से लेकर मार्ग/मौहल्ला स्तर पर सफाई कर्मी की ड्यूटी तथा सम्बन्धित के फोन नं० एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में निकाय द्वारा किस प्रकार समीक्षा की जाती है तथा क्या स्तर है, की समीक्षा।

(10 अंक)

- d. वर्ष में स्वच्छता हेतु जन-जागरूकता के लिए किए गए प्रयासों का विवरण, यथा- स्वच्छता अभियान, गोष्ठियां, जन सेमीनार एवं अन्य आई०ई०सी० कार्यों की समीक्षा। इस प्रकार नगर में निवासरत लोगों/समुदायों की जागरूकता का प्रतिशत।

(10 अंक)

- e. शहर में निवासरत व्यक्तिगत शौचालयों से आच्छादित परिवारों की संख्या एवं सामुदायिक शौचालयों से आच्छादित परिवारों की संख्या, के आधार पर समीक्षा।

(10 अंक)

- f. निकाय में कितनी मौहल्ला स्वच्छता समितियां गठित हैं, इनके द्वारा किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, स्वच्छता समिति के अधीन सफाई कर्मचारियों के द्वारा कूड़े के एकत्रिकरण एवं सड़कों/गलियों की सफाई के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा।

(20 अंक)

- g. प्लास्टिक की रोक के लिए निकाय द्वारा की गयी कार्यवाही एवं प्रयासों की समीक्षा। इस सम्बन्ध में उ०प्र० प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-12 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रशमन के लिए स्थानीय निकाय के प्राधिकार की अधिकारिता के प्रयोग करने के लिए अधिसूचना दिनांक 30-11-2009 के अनुसार निकाय द्वारा की गयी कार्यवाही की समीक्षा।

(10 अंक)

- h. अपशिष्ट के एकत्रिकरण के लिए user charges की क्या व्यवस्था की गयी है, इससे कितनी धनराशि प्राप्त हो रही है तथा इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, का विवरण।

(20 अंक)

- i. प्रतिदिन नगर में कितना कूड़ा एकत्र किया जाता है तथा उसको जैविक एवं अजैविक में पृथक्कीकरण करते हुए किस प्रकार निस्तारण किया जाता है।

(10 अंक)

- j. जैविक अपशिष्ट का treatment, अजैविक अपशिष्ट की recycling & reuse तथा शेष बचे अपशिष्ट का वैज्ञानिक भू-भरण एवं सुरक्षित निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है तथा इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं, का विवरण।

(10 अंक)

- k. शहर के विभिन्न स्थानों यथा- रेलवे ट्रैक, नहर/नाला/नदी के किनारों एवं खुले मैदान, पार्को, सड़क/गलियों के किनारे तथा मलिन बस्ती क्षेत्र में व्याप्त गन्दगी का स्तर तथा की गयी कार्यवाही। इस प्रकार शहर को open defecation free करने के सम्बन्ध में निकाय के प्रयास के उपरान्त वर्तमान स्थिति की समीक्षा।

(20 अंक)

- l. शहर में घरों से door to door collection, बाजार क्षेत्र में shop to shop collection तथा अन्य क्षेत्रों में establishment to establishment collection के माध्यम से कूड़े को एकत्रिकरण करने की क्या व्यवस्था है कितने घर/दुकानें/प्रतिष्ठान इससे आच्छादित हैं तथा आच्छादित नहीं हैं। इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं।

(40 अंक)

- m. टी0सी0एस0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर के आधार पर शिकायत निराकरण के क्रियान्वन व्यवस्था एवं सेवाओं तथा शिकायतों की online व्यवस्था के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों की स्थिति।

(20 अंक)

7.2 अन्य संकेतक

- a. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निकाय के लिए की गयी अनुकूल/प्रतिकूल टिप्पणी का विवरण।

- b. क्या शहर में शुष्क शौचालय विद्यमान है, यदि नहीं तो प्रमाण पत्र।
- c. शहर के सार्वजनिक स्थलों यथा— बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रैनबसेरों, धर्मशालाओं, बाजार आदि के समीप जनशौचालय की उपलब्धता तथा संख्या एवं इनकी सफाई का स्तर। शौचालय किन माध्यमों से संचालित किये जा रहे हैं तथा कितने शौचालयों का संचालन निकाय द्वारा किया जा रहा है। निकाय द्वारा संचालित शौचालय तथा अन्य माध्यम से संचालित शौचालयों की सफाई का स्तर की समीक्षा।
- d. शहर में सफाई कर्मियों की संख्या तथा उक्त में से कितने कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
- e. नगर में ट्रेडिंग ग्राउण्ड की उपलब्धता। उपलब्ध न होने की दशा में निकाय हेतु अन्य शहरों के साथ क्लस्टर के रूप में ट्रेडिंग ग्राउण्ड की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी है अथवा नहीं तथा इसके लिए किये गये प्रयासों की समीक्षा।
- f. नगर में सड़को/गलियों की लम्बाई के सापेक्ष पक्की नालियों/ड्रेनेज की व्यवस्था की समीक्षा।
- g. नगर में ऐसे स्थलों की संख्या जहां जलभराव/गन्दा पानी एकत्र होता है तथा इसके निस्तारण हेतु की गई स्थायी/अस्थायी व्यवस्था का विवरण तथा समीक्षा।